

## भारतीय मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण

### प्रलिस के लयि:

[भारतीय मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण](#), पूंजी खाता वनिमिय, [वशिष वोसट्रो रुपया खाते \(SVRA\)](#), [भारतीय रुपए में अंतरराष्ट्रीय व्यापार नपिटान](#), रुपए में बाह्य वाणजियकि उधार

### मेन्स के लयि:

भारतीय मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण, भारत से जुड़े या भारत के हतियों को प्रभावति करने वाले द्वपिक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्वकि समूह और समझौते ।

[स्रोत: द हट्टि](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से खरीदे गए कच्चे तेल के लयि पहली बार रुपए में भुगतान कयि है, जसिसे भारतीय मुद्रा के अंतरराष्ट्रीयकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है ।

- जुलाई 2023 में, संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक समझौते ने **अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC)** से दस लाख बैरल कच्चे तेल के लयि **इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC)** को रुपए में भुगतान की सुवधि प्रदान की । इसी तरह, कुछ रूसी तेल आयात का नपिटान रुपए में कयि गया ।
- भारत, तेल आयात (85% से अधिक) पर बहुत अधिक नरिभर है, वशिष रूप से इसने यूक्रेन संघर्ष के बाद रूसी तेल वविाद के बीच, अंतरराष्ट्रीय दायतियों का उल्लंघन कयि बना आपूरतकिरत्ताओं में वविधिता लाते हुए सबसे अधिक लागत प्रभावी तेल की सोर्सगि पर केंद्रति रणनीति अपनाया है ।

## रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण क्या है?

- **परचिय:**
  - रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रकरयि है जसिमें सीमा पार वनिमिय में स्थानीय मुद्रा का उपयोग बढ़ाना शामिल है ।
  - इसमें आयात और नरियात व्यापार के लयि रुपए को बढ़ावा देना तथा फरि अन्य चालू खाता वनिमिय के बाद [पूंजी खाता वनिमिय](#) में इसका उपयोग करना शामिल है ।
- **ऐतहासकि संदर्भ:**
  - 1950 के दशक में, भारतीय रुपए का व्यापक रूप से संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर में [वैधानकि नविदि](#) के रूप में उपयोग कयि जाता था ।
  - हालाँकि, वर्ष 1966 तक भारत की मुद्रा के अवमूल्यन के कारण भारतीय रुपए पर नरिभरता कम करने के लयि इन देशों में संप्रभु मुद्राओं की शुरुआत हुई ।
- **रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण के लाभ:**
  - **मुद्रा मूल्य की सराहना:** इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में रुपए की मांग में सुधार होगा ।
    - इससे भारत के साथ काम करने वाले व्यावसायों और व्यक्तियों के लयि सुवधि बढ़ सकती है तथा वनिमिय लागत कम हो सकती है ।
  - **वनिमिय दर की अस्थिरता में कमी:** जब किसी मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण होता है, तो उसकी वनिमिय दर स्थिर हो जाती है ।
    - वैश्वकि बाजारों में मुद्रा की बढ़ती मांग अस्थिरता को कम करने में सहायता प्रदान कर सकती है, जसिसे इसे अंतरराष्ट्रीय वनिमिय के लयि अधिक पूर्वानुमानति और वशिषसनीयता नरिमति की जा सकता है ।
  - **भू-राजनीतिक लाभ:** रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण भारत के भू-राजनीतिक प्रभाव को बढ़ा सकता है ।
    - यह अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मज़बूत कर सकता है, द्वपिक्षीय व्यापार समझौतों को सुवधिजनक बना सकता है, साथ ही राजनीतिक संबंधों को भी बढ़ावा दे सकता है ।
  - **भारतीय अर्थव्यवस्था को मज़बूती:** नपिटान मुद्राओं में वविधिता लाकर, वदिशी मुद्रा के दबाव के वरिद्ध भारत की अर्थव्यवस्था को मज़बूत कयि जा सकता है, साथ ही डॉलर की मांग कम की जा सकती है ।
- **चुनौतियाँ:**

- **ट्रफिनि वरिधाभास:** ट्रफिनि वरिधाभास भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने और रुपए की वैश्विक मांग को पूरा करने के बीच संघर्ष के रूप में प्रकट हो सकती है। इन परस्पर वरिधी मांगों को संतुलित करना देश की आर्थिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बना रुपए को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया में एक चुनौती प्रस्तुत करता है।
  - यह किसी देश की घरेलू मौद्रिक नीतिलक्ष्यों और अंतरराष्ट्रीय आरकषति मुद्रा जारीकर्त्ता के रूप में इसकी भूमिका के बीच संघर्ष का वर्णन करता है।
- **वनिमिय दर में अस्थिरता:**
  - मुद्रा को अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिये खोलने से इसकी वनिमिय दर में अस्थिरता बढ़ सकती है, विशेषकर प्रारंभिक चरणों में। उतार-चढ़ाव व्यापार एवं निवेश पर असर डाल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।
- **आयात लागत पर प्रभाव:** यदिरुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण से वैश्विक बाजारों में मुद्रा की मांग बढ़ती है, तो इससे अन्य मुद्राओं की तुलना में रुपया मजबूत हो सकता है। एक मजबूत रुपया संभावित रूप से चीन और रूस जैसे देशों से आयात की लागत को कम कर सकता है, जिससे व्यापार संतुलन प्रभावित हो सकता है।
- **सीमति अंतरराष्ट्रीय मांग:** वैश्विक वदिशी मुद्रा बाजार में रुपए की दैनिक औसत हसिसेदारी केवल 1.6% के आसपास है, जबकि वैश्विक वस्तु व्यापार में भारत की हसिसेदारी 2% है।
- **परविरतनीयता संबंधी चिंता:** **INR पूरी तरह से परविरतनीय नहीं** है, जिसका अर्थ है कि पूंजी वनिमिय जैसे कुछ उद्देश्यों के लिये इसकी परविरतनीयता पर प्रतबंध है। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त में इसके व्यापक उपयोग को प्रतबंधित करता है।
- **वमिद्रीकरण प्रभाव:** वर्ष 2016 की **वमिद्रीकरण** प्रक्रिया और हाल ही में 2,000 रुपए के नोट को हटाने से रुपए की विश्वसनीयता प्रभावित हुआ है, विशेषरूप भूतान तथा नेपाल जैसे आस-पास के देशों में।
- **व्यापार नपिटान में चुनौतियाँ:** हालाँकि लगभग 18 देशों के साथ रुपए में व्यापार करने का प्रयास किया गया है कति वनिमिय सीमति ही रहा है।
  - इसके अतिरिक्त रुपए में व्यापार करने के लिये रूस के साथ वार्ता प्रगतधीमी रही है तथा मुद्रा मूल्यहरास संबंधी चिंताओं एवं व्यापारियों के बीच अपर्याप्त जागरूकता के कारण इसमें बाधा आ रही है।
- **अंतरराष्ट्रीयकरण की दशा में कदम:**
  - **GIFT सटि में वकिस**
  - **एशियाई समाशोधन संघ (ACU):**
    - एशियाई समाशोधन संघ (Asian Clearing Union- ACU) एक कषेत्रीय भुगतान व्यवस्था है। यह बहुपक्षीय आधार पर अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार लेनदेन के नपिटान की सुवधि प्रदान करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1974 में एशिया के दस केंद्रीय बैंकों द्वारा की गई थी। ACU में वर्तमान में 13 सदस्य देश हैं तथा भारत ACU का सदस्य है।
  - मार्च 2023 में RBI ने 18 देशों के साथ रुपए के व्यापार नपिटान के लिये तंत्र स्थापति किया।
    - इन देशों के बैंकों को भारतीय रुपए में भुगतान के नपिटान के **लिये विशेष रुपी वोस्टरो खाते (Special Vostro Rupee Accounts- SVRA)** खोलने की अनुमति दी गई है।
  - जुलाई 2022 में RBI ने **"भारतीय रुपए में अंतरराष्ट्रीय व्यापार नपिटान"** पर एक परपितर जारी किया।
  - RBI ने रुपए में **बाह्य वाणजियक उधार (विशेष रूप से मसाला बाण्ड)** को सकषम किया।

## वे कौन-से सुधार हैं जिन्हें भारत रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण करने के लिये अपना सकता है?

- **रुपए को अधिक स्वतंत्र रूप से परविरतनीय बनाना:**
  - वर्ष 2060 तक पूर्ण परविरतनीयता के लक्ष्य के साथ वित्तीय निवेश को भारत तथा वदिशों के बीच स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करना।
  - इससे वदिशी निवेशकों को रुपए के सरलता से कर्य तथा वकिर्य की सुवधि मलिंगी, जिससे इसकी तरलता बढ़ेगी एवं यह अधिक आकर्षक बन जाएगा।
- **तारापोर समति द्वारा सुझाए गए सुधार:**
  - **सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन:** इसके तहत राजकोषीय घाटे को 3.5% से कम करना, सकल मुद्रास्फीति दर को 3%-5% तक कम करना एवं सकल बैंकिंग गैर-नपिपादति परसिंपत्तियों को 5% से कम करना का सुझाव दिया गया था।
  - **व्यक्तगित प्रेषण के लिये उदारीकृत योजना:** वदिशी मुद्रा का आदान-प्रदान वाले व्यक्तियों के लिये आसान लेनदेन की सुवधि हेतु व्यक्तगित प्रेषण के लिये एक अधिक उदार योजना की शुरुआत।
  - **कर्मचारी सटॉक वकिलुपों के लिये प्रतबंधात्मक खंडों को हटाना:** कर्मचारियों के सटॉक वकिलुपों को रणियती दरों पर जारी करने से संबंधित प्रतबंधात्मक खंडों को हटाना, सटॉक वकिलुपों से संबंधित लेनदेन एवं संचालन को सरल बनाने की अनुमति देना।
  - **वभाग का नाम परविरतन एवं पुनर्वनियाम:** समति ने नाम बदलने और **वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999** के कार्यान्वयन को संभालने के लिये जमिमेदार वभाग को वनिमिय नयित्रण वभाग से वदिशी मुद्रा वभाग में पुनर्नरिदेशित करने का सुझाव दिया, जिसमें एक दुर्बल तथा अधिक रणनीतिक कार्यबल दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया गया।
- **गहन बॉन्ड बाजार का अनुसरण (Pursue a Deeper Bond Market):** वदिशी निवेशकों और भारतीय व्यापार भागीदारों को रुपए में अधिक निवेश वकिलुप उपलब्ध कराने से इसका अंतरराष्ट्रीय उपयोग संभव हो सकेगा।
- **नरियातकों/आयातकों को रुपए में लेनदेन के लिये प्रोत्साहित (Encourage Exporters/Importers for Transactions in Rupee):** रुपए के आयात/नरियात लेनदेन के लिये व्यापार नपिटान औपचारकितार्ताओं को अनुकूलित करने से काफी मदद मलिंगी।
- **अतिरिक्त मुद्रा वनिमिय समझौतों पर हस्ताक्षर:**
  - श्रीलंका की तरह, भारत को डॉलर जैसी आरकषति मुद्रा का सहारा लिये बना, रुपए में व्यापार और निवेश लेनदेन नपिटाने की अनुमति देना।
    - भारत के पास वर्तमान में किसी भी भुगतान संतुलन के मुद्दे के मामले में समर्थन की बैकसटॉप लाइन के रूप में जापान के साथ 75 बलियन अमेरिकी डॉलर तक की द्वपिकषीय स्वैप व्यवस्था (BSA) है।
- **मुद्रा प्रबंधन स्थिरता सुनिश्चित करना और वनिमिय दर व्यवस्था में सुधार करना:**

